

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] No. 473] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 642(अ).—राष्ट्रपति द्वारा रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के दुर्व्यवहार, अथवा अक्षमता की जांच की प्रक्रिया) नियम, 1991 के नियम 3 (1) के अंतर्गत दी गई मंजूरी के अनुसरण में श्री आर. के. मित्तल, सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण (आर सी टी), की ओर से रेल दावा अधिकरण/पटना में 05.05.2015 से 16.08.2017 तक उनके कार्यकाल के दौरान किए गए तथाकथित कदाचार/दुर्व्यवहार के अभ्यारोपण के आरोपों की जांच करने का निर्णय लिया गया है।

माननीय न्यायाधीश श्री उदय यू. ललित, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय को सक्षम प्राधिकरण द्वारा श्री आर. के. मित्तल, सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण (आर सी टी), की ओर से किए गए कदाचार एवं/अथवा दुर्व्यवहार के अभ्यारोपण के उक्त आरोपों की जांच करने के लिए नामित किया गया है।

जांच की प्रक्रिया इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 2018/टीसी(आरसीटी)/3-3]

विवेक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (जन शिकायत)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2018

G.S.R. 642(E).—In pursuance of the sanction accorded by the President under Rule 3 (1) of the Railway Claims Tribunal (Procedure of Investigation of Misbehaviour, or Incapacity of the Chairman, Vice-

4014 GI/2018 (1)

Chairman and Members) Rules, 1991, it has been decided to conduct an enquiry into the charges of imputation of alleged mis-conduct/mis-behaviour on the part of Shri R. K. Mittal, Member (Judicial), Railway Claims Tribunal (RCT), during his tenure from 05.05.2015 to 16.08.2017 in Railway Claims Tribunal/Patna.

Hon'ble Justice Shri Uday U. Lalit, Judge, Supreme Court of India, has been nominated by the competent authority to conduct an inquiry into the said allegations of imputation of mis-conduct/mis-behaviour on the part of Shri R. K. Mittal, Member (Judicial), Railway Claims Tribunal (RCT).

The process of inquiry will come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 2018/TC(RCT)/3-3]

VIVEK SRIVASTAVA, Executive Director (Public Grievances)